

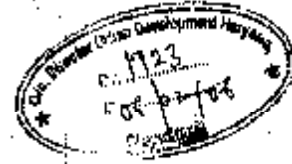
प्रेषक

भारत सरकार
भारत विकास विभाग

सेवा में

हरियाणा राज्य के सभी उपायुक्त 1.

घादी क्रमांक: B/156/88-65-T
दिनांक, यण्डोगढ़ 1-2-2006



क्रमांक
विषय:-

नगरपालिकाओं/नगरपरिषदों की भूमि व दुकानें बेचने बारे ।

उपरोक्त विषय पर सरकार के घादी क्रमांक: B/156/88-65-T
दिनांक 11-6-96 के अनुक्रम में ।

2. सरकार के नोटिस में आया है कि नगरपालिकाओं/नगरपरिषदों की कुछ भूमि, भवन व दुकानें नीचे/तहसीलदारी एवं किराये पर दी हुई है और इत सम्पत्ति से नाममात्र आय प्राप्त हो रही है, उक्त निपटारा दिनांक 31-12-96 तक नहीं किया गया है । इस मामले पर पुनः विचारोपरान्त सरकार ने निर्णय लिया है कि भूमि, भवन तथा दुकानें जो काफी समय से किराये/नीचे व तहसीलदारी पर है और जिन दुकानों भूमि एवं भवन का मासिक किराया 500/- रुपये से कम हो, वह सम्पत्ति वर्तमान कब्जाधारी को बेच दी जाये ।

3. उपरोक्त सम्पत्ति का विषय मूल्य निर्धारित करने हेतु प्रत्येक नगरपालिका/नगरपरिषद के लिए सम्बन्धित उपायुक्त की अध्यक्षता में निम्न कमेटी का गठन किया जाता है :-

1. सम्बन्धित उपायुक्त- अध्यक्ष
2. सम्बन्धित नगरपरिषद/नगरपालिका का प्रधान/प्रशासक- सदस्य ।
3. सम्बन्धित नगरपालिका/नगरपरिषद का सचिव/कार्यकारी अधिकारी -सदस्य ।
4. कार्यकारी अभियन्ता, लोक निर्माण (भवन तथा सड़कें) विभाग - सदस्य ।

4. उपरोक्त के अलावा आपको यह मन्त्रवा भी दी जाती है कि इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने उपरान्त मामला सरकार को स्वीकृति हेतु भेजा जाए ।

5. इसके साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि इस केस में रकसाईज्ज केरिया, अम्बाला सदर एवं नगरपरिषद, अम्बाला सदर को शामिल नहीं किया गया है । अर्थात् उक्त निर्णय नगरपरिषद, अम्बाला सदर के लिए लागू नहीं होगा ।

अधीक्षक कमेटी-1
कृते: भारत सरकार एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
नगर विकास विभाग ।

घादी क्रमांक: B/156/88-65-T

दिनांक: 1-2-2006

एक प्रतिलिपि निदेशक, नगर विकास, हरियाणा को उनके पत्र क्रमांक सी. टी. पी. /2005/स-1/45859, दिनांक 20-10-2005 के तन्दर्भ में सूचनाएँ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

अधीक्षक कमेटी-1
कृते: भारत सरकार एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
नगर विकास विभाग ।

पु. क्रमांक: 8/156/88-6 क-1

दिनांक: 1-2-2006

एक-एक प्रति निम्नलिखित को सूचना के एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है।

1. हरियाणा राज्य की सभी नगरपालिकाओं के प्रधान।
2. हरियाणा राज्य की सभी नगरपालिकाओं के कार्यकारी अधिकारी सचिव।



अधीक्षक कमिश्नर-1

कृते: वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
नगर विकास विभाग।

एक प्रति वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, लोक निर्माण विभाग, भवन तथा सड़कें को सूचना के एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है।



अधीक्षक कमिश्नर-1

कृते: वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
नगर विकास विभाग।

सेवा में,

वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
लोक निर्माण विभाग, भवन तथा सड़कें।

अथा: क्रमांक: 8/156/88-6 क-1

दिनांक: 1-2-2006